

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 5/ 2018

रजिस्ट्रेशन संख्या : 2018/00013

अप्रार्थी / रेसपोण्डेंट्स:-

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

नगर परिषद, बांसवाड़ा जरिये श्री
देवेन्द्रपाल सिंह, प्रभारी अधिकारी
एवं राजस्व निरीक्षक, नगर परिषद
बांसवाड़ा।

बनाम

1. श्रीमती कमला पटेल पत्नि
मणिलाल पटेल निवासी
कॉलेज रोड बांसवाड़ा
2. श्री नरेश तलदार निवासी
सुभाष नगर बांसवाड़ा
3. श्री विरेन्द्र पटेल पिता
मणिलाल पटेल निवासी
कॉलेज रोड बांसवाड़ा

श्री राज कुमार जैन, एडवोकेट

उपस्थित

श्री यशपाल गुप्ता एडवोकेट
श्री नरेश तलदार

निर्णय

अपील अन्तर्गत नियम 15(14), 23 राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन)
नियम, 1974

नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा श्रीमती कमला बाई को भूखण्ड सं.144 के दक्षिण में स्थित खांचा भूमि जरिये पट्टा सं.312 दिनांक 29.04.1989 के द्वारा 705.30 वर्गफीट आवंटित की गई भूमि गैर कानूनी एवं नियम विरुद्ध आवंटन को निरस्त करने अपील


दिनांक :- 18.02.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांत नगर परिषद बांसवाड़ा ने वर्ष 1983 में सुभाष नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं.144 कुल क्षेत्रफल 2050 वर्गफीट जरिये निलामी श्रीमती कमला बाई पत्नि मणिलाल पटेल को विक्रय किया गया। श्रीमती कमला बाई ने वर्ष 1987 में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तात्कालीन मौका स्थिति में नगर परिषद बांसवाड़ा में रखते हुए भूखण्ड के पश्चिम दिशा में 140 वर्गफीट को कम करते हुए तागिर स्वीकृति जारी की गई।

उक्त भूमि के बदले क्षेत्रिय सहायक निदेशक स्थानिय निकाय विभाग उदयपुर के आदेश के अनुसार भूखण्ड सं. 144 के दक्षिण में खांचा भूमि स्थित होने से श्रीमती कमला बाई को 705.30 वर्गफीट भूमि दिनांक 24.04.1989 को आवंटित की गई है। उपरोक्त भूमि पर रेस्पोंडेंट श्रीमती कमला बाई ने भवन एवं चार दिवारी का निर्माण मार्गाधिकार छोड़कर किया है। वर्तमान परिपेक्ष्य में रेग्यूलर लाईन से बाहर होने से सडक सीमा अवरुद्ध होती है। भूखण्ड सं. 144 के दक्षिण में कॉलोनी की सडक एवं भूखण्ड के मध्य भूमि रिक्त स्थित है। कमला बाई ने पर्याप्त चौड़ाई की भूमि मौके पर उपलब्ध नहीं होते हुए सडक सीमा की भूमि को खांचा भूमि बताकर आवंटन करा ली है। जिस कारण सडक की चौड़ाई कम हो गई है तथा आवागमन में असुविधा पैदा हो गई है। इस प्रकार नगर परिषद बॉसवाडा द्वारा श्रीमती कमला बाई को भूखण्ड सं.144 के दक्षिण में स्थित खांचा भूमि जरिये पट्टा सं.312 दिनांक 29.04.1989 के द्वारा 705.30 वर्गफीट आवंटित की गई भूमि गैर कानूनी एवं नियम विरुद्ध आवंटन को निरस्त करने अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेण्ट को समन जारी किया गया। अपार्थी श्री नरेश तलदार की ओर से दिनांक 19.04.2018 को जवाब प्रस्तुत हुआ जिसमें उल्लेख किया गया है कि श्रीमती कमला बाई को किया गया आवंटन न केवल सडक सीमा की भूमि के हस्तान्तरण होने के कारण अपितु नगरीय क्षेत्र में भूमियों के हस्तान्तरण सम्बन्धी 1974 के नियमों के विपरीत होने के कारण प्रारम्भ से ही एक अवैध व शून्य प्रभावी हस्तान्तरण है जो कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 30 के अन्तर्गत एक अवैध हस्तान्तरण है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसे आवंटन के आधार पर की गई पश्चात्वर्ती कार्यवाही यानि विक्रय विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन भी अपने आप में अवैध शून्य प्रभावी होते हैं, इसलिये ऐसे दस्तावेजों को निरस्तीकरण करने की कोई बाध्यता नहीं है। नगर परिषद बॉसवाडा की अपील स्वीकार कराई जाकर प्रत्यार्थी सं.1 को खांचा भूमि के रूप में किया गया आवंटन निरस्त करने निवेदन किया।

दिनांक 03.05.2018 को श्रीमती कमला बाई रेस्पोंडेण्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी वास्ते रेस्पोंडेण्ट श्री नरेश तलदार को पक्षकार की श्रेणी से हटाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब रेस्पोंडेण्ट श्री नरेश तलदार द्वारा दिनांक 13.07.2018 को प्रस्तुत किया।


जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)


दिनांक 11.10.2019 को रैस्पोंडेंट श्रीमती कमला बाई की ओर से प्रार्थना पत्र नियम 15(14), 23 स.न.पा. अधिनियम पट्टा निरस्त करने के विरुद्ध आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब कोई हस्तान्तरण पंजीयन के द्वारा निष्पादित हो जाता है तो उक्त दस्तावेज को निरस्ती का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया। दिनांक 18.11.2019 को रैस्पोंडेंट श्री नरेश तलदार की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित किया गया कि नगरपालिका बॉसवाडा द्वारा खांचा भूमि के नाम से अपीलार्थी कमला बाई को जो हस्तान्तरण किया गया है वह वास्तव में सार्वजनिक सडक की भूमि है एवं सडक की भूमि हस्तान्तरण का नगरपालिका को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हस्तान्तरण पूर्णतया अवैध व शून्य प्रभावी होता है।

दिनांक 16.12.19 को अप्रार्थी श्रीमती कमला बाई की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश नियम 10(2) सी.पी.सी प्रस्तुत हुआ जिसमें रैस्पोंडेंट श्रीमति कमला द्वारा श्री विरेन्द्र पटेल के हक में वर्ष 2013 में रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा हस्तांतरित करने पर पक्षकार बनाने हेतु पेश किया गया जिस हेतु श्री विरेन्द्र पटेल पिता मणीलाल पटेल निवासी कॉलेज रोड बॉसवाडा को पक्षकार बनाने की अनुमति दिनांक 24.01.2020 को प्रदान की गई।

जरिये नोटिस रैस्पोंडेंट श्री विरेन्द्र पिता मणीलाल पटेल निवासी कॉलेज रोड बॉसवाडा को तलब करने पर रैस्पोंडेंट श्री विरेन्द्र पिता मणीलाल पटेल ने (प्रोसिंडिंग में सहवन से रैस्पोंडेंट सं.1 अंकित हुआ है।) ने दिनांक 07.09.2020 को जवाब प्रस्तुत किया कि यह अपील रैस्पोंडेंट श्री नरेश तलदार द्वारा जन सुनवाई को आधार मानकर पेश की है। प्रशासनिक आदेश को अपील का आधार नहीं बनाया जा सकता एवं प्रशासनिक आदेश में वाद प्रस्तुत करने लिखा है। रैस्पोंडेंट श्रीमती कमला बाई को भूखण्ड सं.144 कुल क्षेत्रफल 2050 वर्गफीट वाके कॉलेज रोड बॉसवाडा जरिये निलामी विक्रय किया गया है, जिसका अनुज्ञा पत्र क्रमांक 4929 दिनांक 30.12.1983 से नगरपालिका ने विक्रय किया है एवं रैस्पोंडेंट कमला बाई ने राशि रु.60400/- अक्षरे साठ हजार चार सौ जना करवाई एवं वर्ष 1987 में भवन निर्माण हेतु स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त भूखण्ड के दक्षिण में स्थित खांचा भूमि पट्टा सं. 312 दिनांक 29.04.1989 द्वारा कुल क्षेत्रफल 705.3 वर्गफीट, दोनो का क्षेत्रफल 2755.3 वर्गफीट रैस्पोंडेंट श्रीमती कमला बाई को विक्रय किया गया। लीजडीड

निष्पादन के समय आवंटित खांचा भूमि का कुछ हिस्सा सड़क को टेढ़ा मेढ़ा करने के कारण नगरपरिषद् द्वारा मौके पर आवागमन सुखद बनाने हेतु खांचा भूमि की साईज को कम किया। रेस्पोंडेंट कमला बाई को कुल विक्रय की गई भूमि 2755.3 वर्गफीट भूमि है जिसमें मौके की स्थिति को देखते हुए 2614 वर्गफीट भूमि की लीजडीड दिनांक 06.05.2013 को रेस्पोंडेंट कमला बाई के हक में निष्पादित की। नगरपरिषद् ने रेस्पोंडेंट कमला बाई को 413 वर्गफीट कम दी। जबकि किंमत 2755.3 वर्गफीट की प्राप्त की है। रेस्पोंडेंट कमला बाई ने रेग्युलर लाईन में 10.6 फीट बाहर निकलते हुए सड़क के मार्गाधिकार की भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया है तथा इस सम्बन्ध में रेस्पोंडेंट सं.2 श्री नरेश तलदार ने झुठी शिकायत की है। रेस्पोंडेंट कमला बाई ने अपना दक्षिणी हिस्सा अपने पुत्र विरेन्द्र पटेल को खांचा भूमि दिनांक 01.07.2013 को पजीकृत दान विलेख की है। समस्त भूमि अपीलांत नगरपरिषद् द्वारा ही विक्रय विलेख की गई है। नगरपालिका के कानूनी सलाहकार ने भी राय व्यक्त की कि खांचा भूमि जो कि नगर परिषद् द्वारा ही विक्रय की गई है, तथा आवंटन क्षेत्रीय सहायक निदेशक स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर के आदेशानुसार आवंटित की गई है। ऐसी स्थिति में उसे निरस्त किया जाना सम्भव नहीं है। जब कोई हस्तांतरण पजीथन के द्वारा निष्पादित हो जाता है तो उक्त दस्तावेज निरस्ती का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।

दिनांक 01.02.2021 को अपीलांत ने बहस के दौरान अपने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांत नगर परिषद् बॉसवाडा ने वर्ष 1983 में सुभाष नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं.144 कुल क्षेत्रफल 2050 वर्गफीट जरिये निलामी श्रीमती कमला बाई पत्नि मणीलाल पटेल को विक्रय किया गया। श्रीमती कमला बाई ने वर्ष 1987 में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तात्कालीन मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड के पश्चिम दिशा में 140 वर्गफीट को कम करते हुए तामिर स्वीकृति जारी की गई। उक्त भूमि के बदले क्षेत्रीय सहायक निदेशक स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर के आदेश के अनुसार भूखण्ड सं. 144 के दक्षिण में खांचा भूमि स्थित होने से श्रीमती कमला बाई को 705.30 वर्गफीट भूमि दिनांक 24.04.1989 को आवंटित की गई है। उपरोक्त भूमि पर रेस्पोंडेंट श्रीमती कमला बाई ने भवन एवं चार दिवारी का निर्माण मार्गाधिकार छोड़कर किया है। वर्तमान परिपेक्ष्य में रेग्युलर लाईन से बाहर होने से सड़क सीमा अवरुद्ध होती है। भूखण्ड सं. 144 के दक्षिण में कॉलोनी की सड़क एवं भूखण्ड के मध्य भूमि

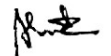

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

रिक्त स्थित है। कमला बाई ने पर्याप्त चौड़ाई की भूमि मौके पर उपलब्ध नहीं होते हुए सड़क सीमा की भूमि को खांचा भूमि बताकर आवंटन करा ली है। जिस कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है तथा आवागमन में असुविधा पैदा हो गई है। साथ ही अपीलेंट के अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 15 (14) के अनुसार आवंटन/ विक्रय निरस्त करने का अधिकार प्रकरण में आवंटन अधिकारी क्षेत्रीय सहायक निदेशक स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर को है। तात्कालिन समय में रेस्पोंडेंट सं. 2 श्री नरेश तलदार की शिकायत पर जिला कलक्टर बांसवाडा के तत्समय निर्देशानुसार इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी।

रेस्पोंडेंट सं.1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलेंट नगरपरिषद् द्वारा ही विक्रय विलेख की गई है। नगरपालिका के कानूनी सलाहकार ने भी राय व्यक्त की कि खांचा भूमि जो कि नगर परिषद् द्वारा ही विक्रय की गई है, तथा आवंटन क्षेत्रीय सहायक निदेशक स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर के आदेशानुसार आवंटित की गई है। ऐसी स्थिति में उसे निरस्त किया जाना सम्भव नहीं है। जब कोई हस्तांतरण पंजीयन के द्वारा निष्पादित हो जाता है तो उक्त दस्तावेज निरस्ती का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अपीलेंट नगरपरिषद् बांसवाडा द्वारा रेस्पोंडेंट सं. 2 की शिकायत के आधार पर विधि-विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

रेस्पोंडेंट सं. 2 श्री नरेश तलदार ने अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करने समय चाहा। दिनांक 08.02.2021 को रेस्पोंडेंट श्री नरेश तलदार तथा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी इनकी ओर से बहस प्रस्तुत नहीं की जिसके कारण बहस बन्द की गई।

हमने अपीलेंट एवं रेस्पोंडेंट सं 1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बांसवाडा द्वारा रेस्पोंडेंट श्रीमती कमला बाई को 705.30 वर्गफीट खांचा भूमि दिनांक 24.04.1989 को आवंटित की। नगर परिषद् बांसवाडा द्वारा दिनांक 06.05.2013 जरिये लीजडीड रेस्पोंडेंट श्रीमती कमला बाई के हक में पंजीकृत करवाया है। दिनांक 01.07.2013 को रेस्पोंडेंट श्रीमति कमला बाई ने अपने पुत्र रेस्पोंडेंट श्री विरेन्द्र पटेल को जरिये पंजीकृत दान विलेख से हस्तांतरित किया। प्रकरण



जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

अनुसार रेस्पोंडेंट सं. 2 को शिकायत है कि रेस्पोंडेंट सं. 1 को गलत आवंटन हुआ है, कई वर्षों पश्चात् इस प्रकार की शिकायत विधि विरुद्ध है। यदि कोई शिकायत थी तो आवंटन के पश्चात् ही सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकते थे। अब इस शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, एवं अपीलांत स्वयं द्वारा भी अपनी पत्रावली में यह रिपोर्ट दी है कि नगर परिषद भी इसे निरस्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार जब कोई हस्तांतरण पंजीकृत दस्तावेज से पंजीयन के द्वारा निष्पादित हो जाता है तो उक्त दस्तावेज निरस्ती क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलेक्टर
बासवाड़ा (राज.)
बासवाड़ा